चुका था। चल

उत्तराखंड से सुरक्षित खनन के तरीके सीखेगा जम्मू-कश्मीर

- उत्तराखंड की खनन नीति के साथ ही सर्विलांस सिस्टम के बारे में लेंगे जानकारी
- पांच अधिकारियों का यह दल आगामी 18 अगस्त को उत्तराखंड पहुंच जाएगा

राज्य ब्यूरो जागरण • देहरादून: उत्तराखंड भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की खनन कार्यों के डिजिटलीकरण एवं निगरानी की व्यवस्था और सुरक्षित खनन के प्रति अन्य राज्य भी आकर्षित हो रहे हैं। इस कड़ी में अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारियों को उत्तराखंड की इस व्यवस्था को जानने के लिए यहां भेजने का निर्णय लिया है। उनके पांच अधिकारियों का दल 18 अगस्त को उत्तराखंड आकर खनन नीति और सर्विलांस सिस्टम का अध्ययन करेगा।

प्रदेश में खनन राजस्व देने वाले प्रमुख विभागों में है। बीते वित्तीय वर्ष में खनन विभाग ने 1100 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया था। सरकार ने सुरक्षित खनन को प्रोत्साहित किया, साथ में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ठोस खनन नीति और सर्विलांस सिस्टम लागू किया है। इसके तहत सभी खनन क्षेत्रों में चेक गेट लगाए गए हैं। इससे यहां से निकलने वाले वाहनों में खनन सामग्री के भार, वाहन का प्रकार व रवन्ना आदि की पूरी जानकारी विभाग के पास रहती है।

सभी चेक गेट पर नजर रखने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम भी बनाया गया है। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी व नैनीताल में इस तरह के 45 चेक गेट लगाने की योजना है। अभी तक विभाग इन स्थानों पर 14 चेक गेट लगा चुका है, जहां से खनन क्षेत्रों से निकलने वाली सामग्री की चोरी पकड़ने के साथ ही तय क्षेत्रों में ही खनन कार्य संपादित कराया जा रहा है। इसका फायदा भी विभाग को मिला है।

इस कारण उसके राजस्व में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। निदेशक खनन राजपाल लेघा ने बताया कि इस संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा संपर्क किया गया था। अब उनकी पांच सदस्यीय टीम 18 अगस्त को उत्तराखंड आ रही है।

दैनिक जागरण
अपने